ईरान, जॉर्डन है। हम और भी काफी जगहों पर अपने प्रोग्राम बना रहे हैं जिनमें नेपाल, बंगलादेश, इंडोनेशिया, मॉरीशस, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, मलावी, जिम्बाब्वे, कांगो, सूडान, घाना, टोगो, नाइजीरिया, कोसोवो, ईस्ट तिमोर है। इनके बाद हमारा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ईरान, बेलारूस, फ्रांस और मैक्सिको के साथ है।

Replacement of telephone exchanges

*403. SHRI R.S. GAVAI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether a number of old and outdated telephone exchanges are in need of replacement by electronic exchanges;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have prepared any plan to replace these old and outdated telephone exchanges;

(d) if so, by when all the exchanges are proposed to be replaced by electronic ones; and

(e) the steps taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI TAPAN SIKDAR): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Out of 32067 telephone exchanges working in the country as on 30.6.2001, there are 1499 electronic exchanges mostly of small and medium capacities which are outdated due to change of technology. The capacity of these outdated exchanges is less than 1% of the total capacity available in the country.

(c) and (d) Yes, Sir. These exchanges are planned to be replaced by Digital Electronic Exchanges by March, 2002.

(e) New Technology/C-DoT exchanges are being allotted to the concerned circles for replacing these exchanges during 2001-2002.

SHRI R.S. GAVAI: Sir, the reply given by the hon. Minister has not taken into account the relevance of the intention with which I put the question. I had put a question: "What is the total number of

outdated telephone exchanges?" The reply given by the hon. Minister relates to the outdated electronic exchanges. My question was: "What was the number of outdated non-electronic telephone exchanges existing as of 30th June, 2001?" In 1999, a reply was given that there were four outdated non-electronic exchanges in Maharashtra, that is, Amaravati, Satara, Dhule and Malegaon. In this connection, I want to know what is the present status of these four outdated non-electronic exchanges in Maharashtra. What are the efforts being made by the Government for converting these outdated non-electronic exchanges into electronic exchanges?

संचार मंत्री (श्री रामविलास पासवान): सभापति जी, जो टोटल नम्बर ऑफ एक्सचेंजेस हैं वे मैंने अपने जवाब में बता दिए हैं। टोटल नम्बर ऑफ एक्सचेंजेस 32,066 है। इसमें 1,499 एनालॉग इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजेस हैं। इन 32,066 में से केवल 1,499 एनालॉग बचे हैं और इसके लिए हमने मार्च, 2002 तक का मैक्सिमम टारगेट रखा है। हम कोशिश करेंगे कि दिसम्बर, 2001 तक जितने भी एक्सचेंजेस हैं—इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजेस ही हैं, एनालॉग हैं लेकिन डिजिटल हैं, हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे और सब जगह रिलायबल मीडिया लगा देंगे।

श्री आर॰एस॰ गवई: सभापति जी, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि टोटल नॉन इलेक्ट्रोनिक आउटडेटेड एक्सचेंजेस कितने हैं। इन्होंने रिप्लाई दिया कि 1,499 हैं It relates to electronic exchanges only. और मैंने यह पूछा कि 1999 में आपने जवाब दिया था कि महाराष्ट्र में ऐसे चार सैंटर हैं जो आउटडेटेड हैं, नॉन इलेक्ट्रोनिक हैं जिनमें अमरावती, सतारा, धुले, मालेगांव हैं। मैंने पूछा है कि आज की स्थिति क्या है? आपने उसे कन्वर्ट किया है या नहीं किया है? मुझे दो ही क्वेश्चन पूछना अलाउड है इसलिए आखिर का सवाल पूछता हूं कि टेली डेंसिटी कंट्री में in urban areas it comes to 3.6 per cent for 100 persons. In rural areas it comes to only 0.6 per cent. This is a very poor percentage. यह डेंसिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग की है खासतौर पर रूरल एरिया, ट्राइबल एरिया और माउंटेन एरिया में?

श्री रामविलास पासवान: सर मैंने जैसे कहा, आपकी कांस्टिट्युयेंसी की फिगर्स मेरे पास नहीं है, उन्हें मैं बाद में भेज दूंगा। लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक 1499 में 398 एनालाग इलेक्ट्रोनिक्स एक्सचेंजेस हैं और इन सब के बारे में मैंने कहा कि इन सब को मार्च 2002 से पहले हम डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे और रिलाइबल मीडिया भी लगा देंगे। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है आप देखेंगे कि वहां मुश्किल से 1 परसेंट बचा है। आप तो जानते हैं कि अभी हमारे पास पांच तरह के एक्सचेंजेज हैं। जो शुरूआत हुई वह मैनुअल से हुई। उसके बाद

एस्ट्राउजर आया जो 90 तक चला। एस्ट्राउजर के बाद क्रासबार आया और अब यह खत्म हो गया है। उसके बाद एनालाग बचा है और अब डिजिटल एक्सचेंज आ गया है। यह एनालाग अब 1 परसेंट बचा है और इसको हमने 2002 तक टाइम बाउंड रखा है। लेकिन 2002 मार्च का समय हमको थोड़ा अधिक लगता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि दिसम्बर तक हम इसको रिप्लेस कर दें।

जहां तक टेली-डेंसिटी का सवाल है यह बात सही है कि हमारी जो टेली-डेंसिटी है, वह संसार के अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है। वर्ल्ड एवरेज 15 पर 100 है। जो बड़े-बड़े कन्ट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं वहां यह 100 परसेंट है। वहां मोबाइल हैं, बेसिक टेलीफोन भी हैं। लेकिन हमारे यहां प्राब्लम यह भी है कि हमारी जो जनसंख्या है, उस दृष्टिकोण से देखें तो हमारे यहां टेलीफोन लाइनों की कमी नहीं है। कुल मिलाकर 3 करोड़ 29 लाख हमारे टेलीफोन हैं और 45 लाख हमारे मोबाइल टेलीफोन हैं। लेकिन जो टेली डेंसिटी के बारे में आपने कहा तो कुल मिलाकर पर 100 पर हमारे यहां 3.6 हैं। यह पिछले साल में डबल हुआ है। गांव का जो आपने कहा, गांव का ठीक है, टेली डेंसिटी बहुत ही कम है, यह 0.93 है। ...(व्यवधान)... इसको हम देख लेंगे। आपने पूछा है कि हमारा टारगेट क्या है जो हमारा जो टारगेट है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि गांव और शहरों को मिलाकर हमारी जो टेली डेंसिटी है, हम उसको 3.6 पर ले जाना चाहते हैं और 2005 तक हम इसे 7 पर 100 पर ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि साढ़े सात सौ करोड़ लाइन हम 2005 तक बिछायेंगे और 2010 तक हम साढ़े 17 करोड़ लाइन बिछायेंगे। जब साढ़े 17 करोड़ लाइन हम बिछायेंगे तो फिर 15 पर 100 टेली-डेंसिटी हो जाएगी और देहात का 2010 तक हमारा जो टारगेट है वह 4 पर 100 का है।

SHRI R.S. GAVAI: He has not replied to my question. My supplementary relates to Maharashtra, Hyderabad, Rajkot, Baroda, Surat, Bangalore, Trivandrum, Jabalpur, Amravati, Satara, Dhulia, Malegon and Jaipur. आपने कहा था कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब, प्रजेन्ट पोजीशन क्या है? यह जो आउट डेटेड हैं इनको कन्वर्ट कराकर इलेक्ट्रानिक्स किए हैं या नहीं किए हैं? You say, "Yes or no".

श्री रामविलास पासवान: सर, माननीय सदस्य ने जो यह प्रश्न किया है यह जनरल प्रश्न किया है। इस नाते स्टेट तक की फिगर्स मेरे पास हैं और स्टेट की फिगर्स मैंने बतला दी हैं। जहां तक माननीय सदस्य की कांस्टिट्युयेंसी का सवाल है, मैं उसके बारे में माननीय सदस्य को बतला दूंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर नहीं हुआ होगा तो वह चार महीने के अंदर हो जाएगा।

SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Sir, in the State of Andhra

Pradesh, there are digital exchanges in important towns like Vijayawada and Vizag. Near these exchanges there are many important places which can be connected. For example, Gannavaram town can be connected to the Vijayawada Exchange. Due to lack of proper planning on the part of the DoT, important towns are left out. Why is it so?

श्री रामविलास पासवान: सभापति महोदय, हमारे पास जो पूरी की पूरी लिस्ट है, दुर्भाग्य से यह बात सही है कि उसमें महाराष्ट्र के बाद, आन्ध्र प्रदेश आता है। जो एनालॉग सिस्टम है वह सब से ज्यादा महाराष्ट्र में है, उसके बाद 2089 आन्ध्र प्रदेश में है, और फिर तीसरे नम्बर पर उड़ीसा और गुजरात आता है। दुर्भाग्य से जहां-जहां से सब से ज्यादा टेलीकाम का विकास हो रहा है, वहां यह प्रोब्लम्स हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा इसको भी हम तीन चार महीने के अन्दर सब जगह सार्ट आऊट कर लेंगे।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि मैं पासवान जी के बढ़ते हुए चरणों में और कार्य में शंका पैदा नहीं करना चाहती हूं लेकिन मैं इतना कहूंगी कि हमारे बीकानेर जिले में छाजूवाला, छत्तरगढ़, दंतोर और तीन पावली में टेलीफोन के कनेक्शन की तारें जुड़ गई हैं लेकिन उसमें टन-टन की आवाज़ नहीं आती, वह बहुत देर तक गम्भीर निद्रा में इस प्रकार सोए रहते हैं जैसे कुम्भकरण सो रहे हों। उसके बावजूद जब हम जी०एम० से शिकायत करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एकमात्र खुशी की लहर भी है और अभिमान भी है, देखो हमारे घर में टेलीफोन लगा हुआ है लेकिन पड़ा रहता है तो इतनी झत्राहट आती है कि इसको क्या करें इससे अच्छा तो बाहर जा कर फैंक दिया जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने सुविधा तो बहुत दी हैं लेकिन इनकी जो गम्भीर निद्रा है, उसको थोड़ा आप जागृत कर दीजिये, मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी।

श्री रामविलास पासवान: ठीक है, इसके लिए एम०ए०आर०आर० सिस्टम जो गम्भीर निद्रा में सोया हुआ है, उसमें अधिकांश वह टावर लगा हुआ है जो एम०ए०आर०आर० टेक्नोलोजी के तहत था। इसलिए उस एम०ए०आर०आर० टेक्नोलोजी को बदल कर हम सब जगह डब्ल्यू०एल०एल० टेक्नोलोजी ला रहे हैं। जब डब्ल्यू०एल०एल० टेक्नोलोजी आ जाएगी तो हमको उम्मीद है कि वह कभी नहीं सोएगा, हमेशा जगा रहेगा। अब सब लोग ज़रा उसमें समर्थन दीजियेगा। कांग्रेस से भी अपील है।

श्री मोहम्मद आज़म खान: टेलीफोन खराब रहेगा और इस बीच जब तक आप टेक्नोलोजी बदलेंगे, इस पीरियड का आप बिल तो इनसे नहीं लेंगे?

श्री रामविलास पासवान: आलरेडी इसमें हमने आदेश दे दिया है कि यदि टेलीफोन सात दिन से ज्यादा खराब रहेगा उस महीने का टेलीफोन बिल नहीं देना होगा।

डा० वाई लक्ष्मी प्रसाद: सभापति महोदय, यह पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने और डिजिटल एक्सचेंज में बदलने की समस्या है। आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना प्रान्त में यह एक विशेष तनाव की स्थिति है आतंकवाद और नक्सलवाद के कारण बहुत से टेलोफोन एक्सचेंज को जलाने की एक विशेष प्रक्रिया जारी है। इसलिए एक विशेष कार्यक्रम के तहत उनके तुरंत पुनर्निर्माण करने की कोई योजना आपने बनाई है या आपके पास कोई विचार है?

श्री रामविलास पासवान: सभापति महोदय, हमारा डिपार्टमेंट जान जोखिम में डाल कर के अपना काम करता रहता है। गुजरात के हमारे साथी बैठे हुए हैं। जिस तरीके से गुजरात में आपदा आई, हमें अपने डिपार्टमेंट पर गर्व है कि 24 घंटे के अन्दर उन्होंने सारे का सारा टेलीफोन सिस्टम खड़ा कर दिया। उसी तरह से चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका हो, चाहे नार्थ ईस्ट का इलाका हो और चाहे त्रिपुरा का इलाका हो, हमारे बहुत से आफिसर्ज़ मारे जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपने काम को ड्यूटी समझ कर के हमारा डिपार्टमेंट करता रहता है। लॉ एंड आर्डर का मामला राज्य सरकार का मामला है और हम लॉ एंड आर्डर की आड़ में यह नहीं कह सकते हैं कि हम कहीं टेलीफोन नहीं लगाएंगे। जहां तक संभव हो रहा है, हम जा रहे हैं।

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अभी दो तीन बार जिक्र किया डब्ल्यू०एल०एल० का। आप भी जानते हैं, सदन भी जानता है, आपका विभाग भी जानता है और अब तो सारी दुनिया जानती है। भारत जैसे गांवों के देश में जिसमें करीब-करीब छः साढ़े छः लाख गांव हैं टेली-डेंसिटी बढ़ाने के लिए हमको कोई न कोई आधुनिक प्रयास करना पड़ेगा और उस प्रयास का एक हिस्सा है डब्ल्यू०एल०एल०। यह तो आपने उत्तर में बताया है कि अभी भी शेष काम है उसको हम सी०डॉट को आबंटित कर रहे हैं। आपने उत्तर के तीसरे हिस्से में दिया है। मै जानना चाहता हूं कि डब्ल्यू०एल०एल० संसार में और किस देश में सफल है या लागू है या नहीं है या यह केवल भारत में इसका प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि हम पहले दूध से जल चुके हैं और खुद आपने स्वीकार किया कि एम०ए०आर०आर० सिस्टम बिलकुल डेड है, मरा हुआ है और जो बड़े-बड़े टावर लगे हुए हैं देहातों में उन पर पंचायतों के सरपंचों की गाय भैंसें बंधी हुई हैं, उनके बच्चों के कपड़े उन पर सूख रहे हैं। वह टॉवर इस काम में आ रहे हैं। डब्ल्यु०एल०एल० पर आप कितना भरोसा भारत के भूगोल को देखते हुए करते हैं? संसार में यह सिस्टम और कहीं लागू है कि नहीं है या केवल हम ही प्रयोग कर रहे हैं?

श्री रामविलास पासवान: सर, दो तरह की अभी तक लेटेस्ट टेक्नालाजी है। एक

जी०एस०एम० टेक्नालाजी है और दूसरी डब्ल्यू०एल०एल० टेक्नालाजी है। जी०एस०एम० टेक्नालाजी की जो दूरी है वह कम है—रेंज कम है। डब्ल्यू०एल०एल० जो है यह अमेरिकन टेक्नालाजी है। इसकी दूरी ज्यादा है। इसमें देहात का जो इलाका है, हम लोगों की जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें कहीं रेगिस्तान का इलाका है...(**व्यवधान**)...

श्री बालकवि बैरागी: क्या अमेरिका में यह सफल है?

श्री रामविलास पासवान: तो यह मान लेते हैं ...(**व्यवधान**)... और हमने टारगेट रखा है कि दिसम्बर, 2002 ईस्वी तक कोई भी ऐसा गांव नहीं रहेगा जहां हम टेलीफोन की सुविधा नहीं दे देंगे। हमारे पास अभी जो लैंड लाइन है, जो केबुल है—केबुल के माध्यम से 2050 तक भी हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो लेटेस्ट जो टेक्नालाजी है उस लेटेस्ट टेक्नालाजी में हमारे पास डब्ल्यू०एल०एल० टेक्नालाजी है और जी०एस०एम० टेक्नालाजी है और उसका हम उपयोग कर रहे हैं।

जहां तक आपने कहा कि किन-किन देशों में यह टेक्नालाजी काम कर रही है—तो यह टेक्नालाजी चाइना में काम कर रही है, यह टेक्नालाजी कोरिया में काम कर रही है और दूसरी जगहों का हमारे पास नहीं है। लेकिन नहीं भी कहीं काम करे तो हम देश को डिजिटल डिवीजन में नहीं रख सकते हैं कि एक तरफ शहर जो हैं वे टेक्नालाजी के मामले में आगे बढ़ते जाएं और गांव टेक्नालाजी के मामले में पीछे चलते जाएं और मिनिमम टेलीफोन की सुविधा वहां न हो। इस दृष्टि से हमने अभी 6 लाख डब्ल्यू०एल०एल० का आदेश दिया है। जितने भी गांव हैं—4 लाख 10 हजार गांवों में अभी तक टेलीफोन की लाइनें लगी हैं। 6 लाख 7 हजार कुल मिलाकर गांव हैं और 4 लाख 10 हजार गांवों में से 2 लाख 11 हजार गांवों में मार टेक्नालाजी है, उसको भी हम बदलेंगे और नये गांवों में भी टेलीफोन लगाएंगे। यह टारगेट हमको 2002 दिसम्बर, तक पूरा करना है। इसलिए अभी तक जो टेक्नालाजी निकली है—लेटेस्ट टेक्नालाजी—उसमें डब्ल्यू०एल०एल० से बढ़िया कोई टेक्नालाजी नहीं है। भविष्य में जो आपकी शंका है कि यह टेक्नालाजी कितना काम करेगी—मैं कहता हूं कि मार टेक्नालाजी में भी राजस्थान का इलाका है जहां उनसे एग्रीमेंट किया गया था मेन्टिनेंस का। वहां वे अधिकांश जगहों पर अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हुई थी—उनके साथ मेन्टिनेंस का कोई एग्रीमेंट था ही नहीं। इसलिए उस टेक्नालाजी का किसी को पता नहीं था। इसलिए वह अधिकांश जगहों पर खराब पड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि यह जो टेक्नालाजी है यह टेक्नालाजी रिलायबुल भी है और इस टेक्नालाजी के माध्यम से हम टेली डेंसिटी को भी बढ़ाएंगे और गांवों को भी कवर करेंगे।

SHRI DRUPAD BORGOHAIN: The hon. Minister has said that

there are 1,499 electronic exchanges, mostly of small and medium capacity, which are outdated due to change of technology. The capacity of these outdated exchanges is less than one per cent of the total capacity available in the country. I would like to know from the hon. Minister what the percentage is of such type of outdated exchanges in the North-Eastern Region. Secondly, I feel that telephone connections on priority basis, out of MPs' quota, are not given on time in the Assam Telecom Circle. It happens so particularly in the Jorhat-TDM area. What has to be done? The Minister may kindly inform us.

श्री रामविलास पासवान: केवल इस तरह का एक ही एक्सचेंज बचा है टोटल नार्थ ईस्ट में। जहां तक एम०पी० कोटे का सवाल है तो मैंने कहा है कि जो हमारा डब्ल्यू०एल०एल० का आया है उसमें हमने जिनको टाप प्रायोरिटी पर रखा है उसमें एम०पी० कोटे को रखा है, हमने विलेजेज को रखा है और उसके बाद जब बचेगा तब हम कनेक्शन प्रायोरिटी के आधार पर उनको देंगे।

Import of rice by Bangladesh

*404. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Bangladesh has placed restrictions on the import of rice from India;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action Government have taken to find alternate markets for the export of rice from West Bengal where the price of rice has fallen due to "warehouse clearance" for the arrival of new harvest?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No restriction has been imposed by the Government of Bangladesh on import of rice from India. The National Board of Revenue has however, issued an order that rice can be imported only